RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 30 जून, 2016 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 13, अंक : 1

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

अप्रैल, मई और जून गर्मी के महीने कहलाते है और उस हिसाब से अप्रैल/मई तो खूब तपे और जून का महीना भी बेहिसाब गर्मी दिखा रहा है।

आलू के भाव धीरे–धीरे तेजी की ओर बढ़ रहे हैं। इस तेजी को देखते हुए आलू व्यापारियों ने और आलू के बड़े भण्डारणकर्ताओं ने अपने आलू को धीरे–धीरे बेचना शुरू कर दिया है और इसी कारण से आलू की निकासी आगरा और फर्रूखाबाद क्षेत्र में अच्छी खासी हुई। आगरा क्षेत्र में तो मई महीने में 10 से 12 प्रतिशत निकासी का अनुमान है जबकि Kolkata क्षेत्र में 8–10 प्रतिशत निकासी का अनुमान लगाया जा रहा है। पूर्वी व मध्य उत्तर प्रदेश में आलू की निकासी बहुत कम है। कुछ क्षेत्रों में तो आलू निकलना भी शुरू नहीं हुआ है। किसान भण्डारणकर्ता आलू की निकासी में दिलचस्पी बिलकुल ही नहीं ले रहा। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि आलू की निकासी कुछ रुक रही है।

→

मण्डियों में माल अधिक होने के कारण और मण्डियों में आलू कम पहुँचने के कारण, आलू का बाजार तेजी की ओर जा रहा है जिसके कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू के थोक व फुटकर भाव पर रोक लगाई है। एक समाचार केन्द्र के अनुसार थोक में आलू का भाव 700 रू प्रति पैकेट, डाला आलू से ऊपर नही होगा। वही फुटकर मे 18 रू प्रति किलो के हिसाब से बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। साथ में सूखे आलू के ऊपर कही रगड़ कर रंग करने पर भी 20 जून से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। हम पर इस समाचार की अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है फिर भी लगता है यह सत्य है, इस तरह के प्रतिबन्ध से यह तो अवश्य होगा कि आलू की बिक्री मध्यम पड़ जायेगी, जिसका कि आगे चलकर कोई भी रूप हो सकता है। हमारे विचार से अभी आलू में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका काफी बड़ा दारोमदार हासन के आलू पर है। यदि हासन का आलू का उत्पादन तगड़ा होता है तो भण्डारणकर्ताओं को परेशानी हो सकती है।

इसके विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार आलू की निकासी पर विशेष चिन्तित है। आलू अधिकारियों के आकड़ों के अनुसार आलू की निकासी बिलकुल संतोषजनक नहीं है और वह भविष्य में काफी परेशानियों का अन्दाजा लगा रहे हैं। इस विषय को लेकर अगले माह के शुरू में कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश के सामने एक मीटिंग का प्रस्ताव भी गया है, जिससे सरकार को पूरी तरह से सचेत किया जा सके और शीतगृहों में भण्डारित आलू को जल्दी से जल्दी कैसे निकालने की व्यवस्था हो, ऐसा ना हो कि कुछ आलू शीतगृहों में ही रह जाए।

इन सब बातों को देखते हुए हम भण्डारणकर्ताओं को यही सलाह देंगे कि भण्डारित आलू की बिक्री हर भाव पर करते रहें। यदि आपके शीतगृह में भण्डारित आलू सुरक्षित रहता है तो इतनी बड़ी परेशानी तो नहीं आयेगी जितनी की माल खराब हो जाने की दशा में आती है। इस समय आलू की देखभाल बहुत जरूरी है। खास तौर से आप सब देख ही रहे होंगे कि बिजली के बार–बार जाने की शिकायत काफी है। जब आती भी है तब काफी देर तक Low voltage की शिकायत रहती है जिस कारण बिजली की मोटरों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यह सबको देखते हुए आलू की देखभाल और भी जरूरी हो जाती है।

आप सब जानते ही हैं कि अगले माह 16–17 जुलाई, 2016 को आगरा में फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया व कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की मीटिंग →

होने जा रही है, जिसमें बडी संख्या में शीतगृहस्वामियों के आने की उम्मीद है। विशेषतः मुम्बई, गुजरात से। आशा है कि 16 जुलाई को मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश उपस्थित होगे वा 17 जुलाई को केन्द्रीय कृषि मंत्री की आने की पूरी सम्भावना है। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की ओर से कुछ मागे मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को दी जाने की तैयारीया की जा रही है, शीतगृह लाईसेन्स के नवीकरण को समाप्त किए जाने की माँग मुख्य है। यदि पूरी तरह नवीकरण समाप्त करने की सम्भावना ना हो तो इसे पाँच वर्षो से बढ़ाकर 10 वर्ष अवश्य किया जाना चाहिए। हमारी दूसरी माँग आलू पर से मण्डी टैक्स समाप्त करने की है। इस मण्डी टैक्स से आलू किसानो को बहुत अधिक उतपीड़न हो रहा है विशेषतः उन किसानों का जो स्थानीय मण्डियों के अलावा अन्य प्रदेशों की मण्डियों में आलू ले जाते है या फिर बिक्री के लिए आलू ले ही नहीं जाते। हमारी अन्य माँग में कोल्ड स्टोरेज एक्ट 1976 पर पुनः विचार करने की भी है, यह एक्ट काफी पुराना हो चुका है जिसमें कई धाराएँ ऐसी है जो व्यर्थ में शीतगृहस्वामियों को परेशान करती है। आगे देखिए सरकार किन–किन बातों को मानती है।

सौर्य ऊर्जा के सम्बन्ध में :

हमारे अनेक सदस्यों से हमें बार–बार सौर्य ऊर्जा के सम्बन्ध में सवाल पूछे जा रहे है। इसके बारे में हमने अपनी पिछली दो पत्रिकाओं मे लिखा भी है। अभी भी हम प्रयत्न कर रहे है कि इस सम्बन्ध में कुछ वक्ताओं को आगरा में 16/17, जुलाई, 2016 की मीटिग में बुलाए और यह भी प्रयास किया जा रहा है कि वहॉ पर सौर्य ऊर्जा के सामान के विक्रेताओं को भी बुलाया जाए जिस से हमारे सदस्य सौर्य ऊर्जा के बारे मे विस्तार से समझ सके।

हमारे देश में करीब–करीब हर जगह सूर्य की रोशनी काफी मात्रा में रहती है अतः सौर्य ऊर्जा सम्बन्धी उपकरण लगाना अच्छा ही रहेगा।

इस समय सौर्य ऊर्जा उपकरण शीतगृहों में छतो पर लगाए जाते है। यदि छत पक्की है तो बहुत अच्छा रहता है लेकिन यदि लोहे की चादर या सीमेन्ट की चादर की बनी है तो देखना पड़ेगा कि वह कितनी मजबूत है और उसका कितना भाग दक्षिण दिशा की तरफ झुका हुआ है क्योंकि हमारे देश में सूर्य की किरणें अधिकांश समय दक्षिण दिशा में ही रहती है। इन छतों पर यह भी

→

देखना आवश्यक होता है बराबर में किसी पेड़ या बड़ी बिल्डिंग की छाया तो इस छत पर नहीं पड़ रही है जिससे कि सूर्य की किरणों के आने में बाधा पड़ती हो। आमतौर से 100 kw system के लिए 700 square metre सपाट जगह की जरूरत पड़ती है। यह जगह चाहे छत पर हो या फिर खाली जमीन पर।

सौर्य ऊर्जा पैदा करने वाल पैनल के अन्दर सौर्य ऊर्जा सैल लगे होते है जिन पर सूर्य की किरणे पड़ती है और फिर उनसे बिजली उत्पन्न होने लगती है। इस बिजली को एक सरकट से जोड़ कर बिजली लेने वाल सिस्टम से जोड़ दिया जाता है, वह चाहे शीतगृह का सिस्टम हो या फिर बिजली स्पलाई ग्रिड का।

अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बिजली उपभोक्ताओं को यह सुविधा दे दी है कि यदि वह सौर्य ऊर्जा से बिजली बनाते है तो सप्लाई ग्रिड में बिजली दे सकते हैं जिससे खर्च किए हुए बिजली में वापसी मिल जाती है, जैसे यदि आपने ग्रिड से 1000 यूनिट बिजली ली है और ग्रिड में सौर ऊर्जा से उत्पादित 800 यूनिट वापस भेज दी है, तो आपको केवल 200 यूनिट का बिल देना पड़ेगा। यदि आप ज्यादा बिजली ग्रिड में दे देते है, जितनी की आपने ली है उससे ज्यादा तो आपको ज्यादा दी हुई बिजली के पैसे बहुत कम मिलेंगे। इसके लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार की सोलर पावर पर आई पॉलिसी को पढ़ें। यह नेट पे मिल जायेगी। इस प्रकार की सुविधा को Net Metering कहते है। इसके लिए एक अलग मीटर लगता है।

इस प्रकार के सिस्टम में जब आपकी ग्रिड से बिजली नहीं आयेगी तब आपका Solar Power System भी काम नहीं कर पाता। इसके लिए थोड़ा Battery Backup देना पड़ जाता है या फिर generator की मदद लेनी पड़ती है। पूरी तरह से उत्पादित बिजली को Battery में स्टोर करने पर काफी कीमत हो जाती है और Battery का रख–रखाव भी बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन जहाँ पर सरकारी बिजली की Supply है ही नही वहाँ पर Battery की मदद लेनी ही पड़ेगी। यह अवश्य ध्यान दें कि सौर्य ऊर्जा केवल उसी समय बनती है जब सूरज चमक रहा होता है तथा यह मानकर चलना पड़ता है कि सौर्य ऊर्जा का उत्पादन वर्ष के औसत 300 दिन ही होता है ना की 365 दिन। हिसाब लगाने पर यह लगता है कि सौर्य ऊर्जा के संयंत्र लगा लेने के बाद पूरे खर्चे की अदायगी 7 से 8 साल में हो जायेगी। इस संयंत्र की आयु औसतन 25 वर्ष होती है। अतः बाकी के वर्ष बहुत ही कम खर्च में गुजरेंगे। →

जार्ज क्रम ने कभी पोटेटो चिप्स का पेटेंट नहीं लिया। यही चिप्स आज दुनिया में सबसे ज्यादा चाव से खाया जाता है।

गुस्से में बना डाली पोटेटो चिप्स

एक भूल और गुस्से में की गई प्रतिक्रिया भी कारगर साबित हो सकती है। दुनियाभर में चाव से खाई जा रही पोटेटो चिप्स पर यह बात साबित होती है। न्यूयॉर्क के शेफ जॉर्ज क्रम ने एक प्लेट फ्राइड पोटेटो एक कस्टमर के लिए तैयार की थी। लेकिन कस्टमर ने पोटेटो प्लेट वापस भेज दी। उसका कहना था कि चिप्स मोटी है और उसे अधिक फ्राय करना चाहिए। जब जॉर्ज ने उसके मुताबिक इसे बनाकर भेजा तो ग्राहक ने फिर वापस कर दिया। उसने ऐसा बार–बार किया। क्रम ने गुस्से में चिप्स को कागज की तरह पतला कर दिया। उन्होंने पत्थर की तरह कड़क कर देना चाहा। लेकिन इस बार चिप्स कस्टमर को पसंद आई। ये चिप्स इतनी हिट हुई कि बाद में क्रम ने इसी खासियत के साथ अपना रेस्त्रां खोला।

यह समाचार हमे श्री हसंमुख जैन गाधी, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने भेजा है।

शोक संदेश

मान्यवर,

बड़े दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूज्य पिताजी श्री मेघराज तलरेजा का देहावसान दिनांक 1 जून 2016 दिन बुधवार को हो गया है। उनकी आत्मा की शान्ति हेतु दिनांक 13 जून 2016 दिन सोमवार को अन्तिम अरदास प्रातः 10 बजे, हवन पूजन एवं शान्तिभोज दोपहर 2.00 बजे निज निवास 562–के, निर्मल राज (पुलिस अधीक्षक आवास मार्ग), सिविल लाइन्स, रायबरेली में सम्पन्न होगा।

उक्त अवसर पर सम्मिलित होकर दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

शोकाकुल परिवार :
निर्मला तलरेजा (पत्नी)
हिना एवं विशाखा तलरेजा (पुत्रवधू)
रागिनी एवं डी.सी. चन्दानी, कल्पना एवं मनोहर गुरनानी
रेनू एवं हरीश लालचन्दानी, मधु एवं प्रकाश कालानी
आकृति एवं समीर सब्बरवाल, देवर्षि, विशाल, एकता, रितु
मोहिता, नमिता, तनीषा, रोहित, करन, रजत, सार्थक, भव्य

पुत्रगण :
विमल तलरेजा
मोबाइल : 9415034051
जय तलरेजा
मोबाइल : 9415436573

एक और पत्रिका ने हमारे द्वारा लिखित संदेश प्रकाशित किया है। CW Construction World एक अंग्रेजी की प्रसिद्ध पत्रिका है जिसमें शीतगृहों के भविष्य के बारे में अपने विचारो के साथ हमारे विचारों को प्रकाशित किया है। जिसे हम अपने सदस्यों के लिए यहाँ दे रहे हैं। क्योंकि यह संदेश अंग्रेजी में है इसलिए हम इसे हिन्दी में भी विस्तार से बता रहे है।

Hot prospects for cold stores

Growing at a compounded annual growth rate (CAGR) of 26 per cent in market value, the temperature-controlled warehousing market is likely to cross Rs 600,000 crore by 2017, according to ASSOCHAM. In capacity, the space is expected to grow at a CAGR of 13 per cent to touch 47 mt by 2017, from 35 mt in 2014.

Mahendra Swarup

About 40 per cent of this capacity lies in Uttar Pradesh with West Bengal ranked a distant second (23 per cent), followed by Punjab (5.5 per cent), Gujarat (5.2 per cent), Bihar (4.7 per cent), Andhra Pradesh (3.7 per cent), Madhya Pradesh (3.3 per cent), Maharashtra (2.2 per cent) and Karnataka (1.7 per cent).

Cold storages can be either single-produce stores or multipurpose.

"Eighty per cent to 85 per cent of existing cold storages in India are for a single agri produce like potatoes, applies, red chillies, etc," says **Mahendra Swarup, President, Federation of Cold Storage Associations of India**. He expects new facilities to come up in rural locations near the producing belts because high land acquisition cost in cities precludes such investments. "Of late, we have seen the closure of several cold stores in Lucknow, because that land is more profitably used for real-estate development," he adds. "A new cold store of 80,000 to 100,000 quintals capacity would cost Rs 5 crore excluding the land cost."

Multipurpose cold storages account for a fourth of the existing cold store capacity but contribute just over half of the revenue, as per ASSOCHAM, which is contrary to Swarup's views. He believes the scope for multipurpose cold storages is good even if they are currently facing hard times owing to low demand.

TCI has recently forayed into multipurpose temperature controlled warehousing, inaugurating its first state-of-the-art cold chain warehouse on Pataudi Road, Gurgaon, in the NCR region. "The new facility will store grocery products, fruits and vegetables, pharmaceuticals, QSR, milk and dairy, marine and meat produce and specialty chemicals, as well as offer value-added services like cutting, dicing, mixing, packing and processing," says **Jasjit Sethi, President & CEO, TCI Supply Chain Solutions**.

"TCI plans to create a nationwide cold chain logistics network comprising five large-scale cold storage facilities by 2020, well supported by distribution and logistics services to provide customers with efficient, cost-effective solutions," says **Vineet Agarwal, Managing Director, TCI Group.**

हमारे विचार से भारत में अधिकाश भण्डारण आलू, सेब, लाल मिर्च, आदि का ही होता है। अब बड़े शहरो के पास के गाँव में जहाँ की जमीन की कीमत कम है और अधिक शीतगृह लगने की सम्भावना है। बड़े शहरों में जहाँ कि जमीन के दाम बहुत अधिक बढ़ते जा रहे है शीतगृहस्वामी अपने कोल्ड स्टोरेज को हटा कर जमीने बेच रहे हैं क्योंकि इतनी महँगी जमीनों के अनुपात में शीतगृह का धन्धा लाभदायक नहीं रह जाता। इस समय मल्टी–पर्पस Multipurpose शीतगृहों की माँग कम है, परन्तु भविष्य में इसकी माँग बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी।

नए शीतगृहों के लिए बिजली की Duty के छूट के सम्बन्ध में सरकारी आदेश :

दिनांक 21.1.2010 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश प्रकाशित किया था जिसके अन्तर्गत 2010 नई इकाईयों को बिजली की Duty से दस वर्ष के लिए छूट दी गई है और यदि Pioneer इकाई है तो उसे छूट 15 वर्ष तक के लिए लागू रहेगी।

हम यहाँ यह सूचना हिन्दी वा अग्रेजी मे प्रकाशित कर रहे है जिस से हमारे सदस्यों को भली प्रकार से विषय स्पष्ट हो जाए। हमें यह सरकारी आदेशों की सूचना श्री मोहित अग्रवाल, मालिक, शिवांग कोल्ड स्टोरेज, सासनी, हाथरस ने भेजी है। इसके लिए हम उनके आभारी है।

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1765/24-3-2009-2000 (124)/09, dated January 21, 2010.

NOTIFICATION

No. 1765/24-3-2009-2000 (124)/09
Lucknow : Dated : January 21, 2010

Whereas the Industrial and Service Sector Investment Policy, 2004 has been approved by the Cabinet in its meeting dated February 19, 2004.

And Whereas in para 3-4-2-9 of the said Policy it has been provided that all new units →

shall be admissible for exemption from the Electricity Duty for a period of ten years and all such units as are declared pioneer units shall be admissible for exemption from the Electricity duty for a period of fifteen years.

Now, therefore with view to implementing the said policy, the Governor, in exercis of the powers under sub-section (4) of section 3 of the Uttar Pradesh Electricity Duty Act 1952 (U.P. Act no. 33 of 1952) is pleased to direct that all new industrial units and all such new units as are declared as Pioneer Units shall be exempted from Electricity Duty for a period of ten years and fifteen years respectively.

By Order,

(Navneet Sehgal)

Secretary

उत्तर प्रदेश सरकार

ऊर्जा अनुभाग–3

संख्या : 1765/24–3–2009–2000 (124)/09

लखनऊ : दिनांक 21 जनवरी, 2010

अधिसूचना

चूँकि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 का अनुमोदन मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2004 को अपनी बैठक में किया जा चुका है।

और चूँकि उक्त नीति के प्रस्तर 3.4.2.9 में वह प्रावधान किया गया है कि समस्त नई इकाईयों को दस वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट अनुमन्य रहेगी और अग्रणी इकाई के रूप से घोषित ऐसी समस्त इकाईयों को यह छूट पन्द्रह वर्ष के लिए अनुमन्य होगी।

अतएव, अब उक्त नीति को कार्यान्वित करने की दृष्टि से राज्यपाल, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह निदेश देते है कि समस्त नई औद्योगिक इकाईयों और अग्रणी इकाई के रूप में घोषित ऐसी समस्त नई इकाईयों को क्रमशः दस वर्ष और पन्द्रह वर्ष के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट रहेगी।

आज्ञा से

(नवनीत सहगल)

सचिव

संख्या : 1765(1)/24–3–2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. सचिव, विद्युत नियामक आयोग, उ.प्र. लखनऊ।
3. अध्यक्ष/सह प्रबंध निदेशक, उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि, लखनऊ।
6. प्रबंध निदेशक, उ.प्र. जल विद्युत निगम लि. लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक, उ.प्र. राज्य विद्युत वितरण निगम लि. लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, उ.प्र. विद्युत पारेषण निगम लि. लखनऊ।
9. प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि., लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि., वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि., मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि., आगरा।
10. प्रबंध निदेशक, कानपुर इलेक्ट्रिक सप्ताई कम्पनी लि. (केस्को), कानपुर।
11. कार्यवाहक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
12. औद्योगिक विकास अनुभाग–1/औद्योगिक विकास अनुभाग–6/लघु उद्योग अनुभाग–4/लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग–4, उ.प्र. शासन लखनऊ।
13. संयुक्त अभिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12–सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
14. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना संख्या–1765/24–3–2009–2000 (124)/09, दिनांक जनवरी, 2010 के अंग्रेजी रूपान्तरण सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत अधिसूचना को उ.प्र. के असाधारण गजट के आगामी अंक में विषयों परिशिष्ट, भाग–4, लखनऊ (ख) में शीघ्र प्रकाशित कराकर 500 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(राजकमल गुप्ता)

विशेष सचिव

भारत सरकार का अनूठा प्रयास :

भारत सरकार ने आलू की कमी को लम्बे समय तक समाप्त करने के लिए दूरगामी कदम उठाने का फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से न केवल जनता को फायदा पहुँचेगा बल्कि इस कदम के अन्तर्गत सरकार ने Africa के देशों मे जहाँ पर दालों का उत्पादन काफी अच्छी मात्रा में है Contract Farming कराने का फैसला लिया है।

इस Contract Farming के अर्न्तगत भारत की Company Africa मे किसानों को उन्नत बीज देगी वा अन्य सुविधाएँ देगी और उसके बाद उत्पादित दाल को एक निश्चित दर पर खरीद लेगी। वही दाल भारत को निर्यात कर दी जायेगी। इस प्रकार जनता का फायदा होगा और साथ में शीतगृह उद्योग को भी कुछ लाभ मिलने की आशा है क्योंकि आयातित दाल को शीतगृहों में सुरक्षित रखना पड़ सकता है।

भारत सरकार का बहुत ही उन्नतशील फैसला :

भारत सरकार ने विदेशों की कम्पनी को भारत मे Food Processing Udyog लगाने पर पूर्णा विदेशी मुद्रा लगाने की छूट दे दी है, लेकिन यह बन्दिश रहेगी कि वह भारत में उत्पादित खाद्य पदार्थों का ही उपयोग कर सकेंगे। इस समाचार से यह आशा की जा रही है कि अनेक Food Processing Udyog के साथ आलू पर आधारित उद्योगों में विशेष प्रगति होगी। बड़ी मात्रा में आलू चिप्स, आलू पाउडर बनने लगेगा जिससे जनता को तो फायदा होगा ही आलू का खर्च भी बहुत बढ़ जायेगा जिससे आलू उत्पादन किसानों को विशेष लाभ होगा।

आन्ध्र प्रदेश के आमों के लिए विशेष सुविधाएँ :

आन्ध्र प्रदेश उद्यान विभाग का वहाँ के आमों को विशेष लाभ देने वाला बनाने के लिए ठोस प्रयत्न किए जा रहे है। इस समय कम आम की पैदावार, पानी ज्यादा जरूरत, बिजली का ज्यादा लगना और महँगी लेवर वा बैकों का बढ़ा हुआ ब्याज आम की फसल को बेचने मे बहुत ज्यादा महँगा कर देता है। इन सबके सुधार की प्रक्रिया अब शुरू की जायेगी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इसका पूरा लेखा–जोखा इकटठा किया है और इस सम्बन्ध में नए शीतगृहों की स्थापना का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे कि आम सुरक्षित रखे जा सके। आम पर आधारित उद्योग भी स्थापित किया जा सके।

→

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@fcaoi.org , Website : http://www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Ashish Guru,** Senior Vice President, **Patit Paban De** - Vice President (North), **Mukesh Kr. Aggarwal** - Vice President (Delhi) and Co-ordinator Government Affairs, **Hansmukh Jain Gandhi** - Treasurer and Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination, **Ujjal Singh Bajwa** - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - Hony. Secretary, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South), **Rakesh Garg** - Co-ordinator Government and International Affairs

TOGETHER WE PROGRESS

उत्तर प्रदेश :

आलू की निकासी पश्चिम क्षेत्र के अर्थात मुख्यतः आगरा वा फर्रूखाबाद क्षेत्र में अच्छी है जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी कम है। आलू के भाव अच्छे चल रहे हैं और अभी करीब 20/25 जुलाई तक अच्छे रहने की उम्मीद है। अगस्त के मध्य तक हासन का आलू बाजारों में आने लगेगा इस कारण बाजार के भाव कुछ पहले से बिगड़ना शुरू हो सकते हैं।

सम्पूर्ण भण्डारित आलू की निकासी से अनुपात में कुछ भी कह पाना कठिन हो रहा है कि भविष्य कैसा रहेगा।

हरियाणा :

हरियाणा में आलू की निकासी काफी कम सुनी जा रही है परन्तु जून माह के अन्त तक इसके तेजी में आ जाने के आसार है।

बिहार :

बिहार में आलू की निकासी काफी मध्यम गिनी जा रही है क्योंकि शायद बिहार के आलू को उत्तर प्रदेश के आलू से Competition का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी अगले माह से बिहार में निकासी तेज होने की सम्भावना है।

पश्चिम बंगाल :

यहाँ पर आलू का भण्डारण भी करीब क्षमता का 12 प्रतिशत कम हुआ है। आलू निकासी की रफ्तार काफी कम है। इसका कारण पश्चिम बंगाल में भण्डारित आलू की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं गिनी जा रही है। वैसे बाजारों में माँग अच्छी है और हो सकता है अगले महीने में निकासी काफी तेजी पकड़ ले और पिछले गैप को भी पूरा कर ले। हो सकता है आलू निकाली पर पश्चिम बंगाल के रेट कण्ट्रोल कम भी असर पड़ रहा है।

→

आगरा में होने वाली 16 व 17 जुलाई, 2016 की मीटिंग के सम्बन्ध में :

बडे हर्ष का विषय है कि आगरा की होने वाली मीटिंग में American Embassy, New Delhi ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है। उनके प्रतिनिधि आगरा पहुँचे, जहाँ हमारे आगरा के शीतगृहस्वामियों ने उनका दिल से स्वागत किया व भारतीय शीतगृह उद्योग के बारे में विस्तार से बताया। उन्हें कुछ शीतगृहों का भ्रमण भी कराया गया।

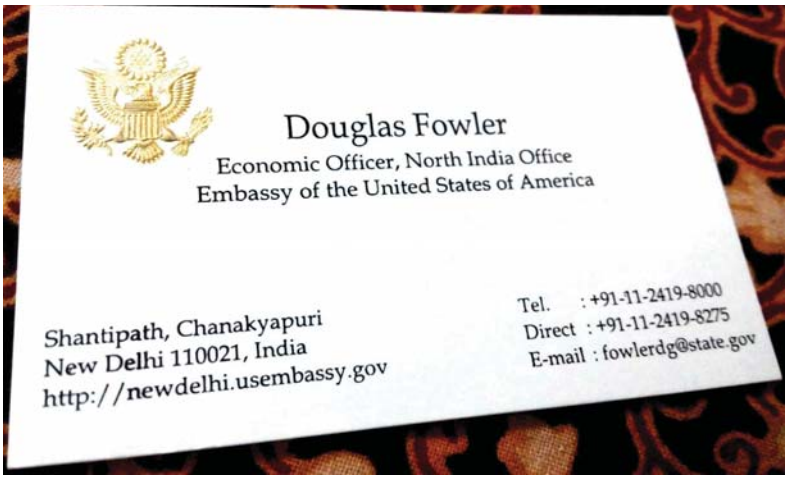

इस सबसे वह बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने आगरा की मीटिंग में आने और विस्तार से देखने व समझने की इच्छा जताई। इसके लिए हम उन्हें आमन्त्रित भी कर रहे है। ऊपर चित्र में आगरा कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि American Embassy, से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए दिखाए गए हैं। नीचे दूसरे चित्र में अमेरीकी Economic Office, North India Office का कार्ड भी दिखाया जा रहा है। हमें आशा है कि इस तरह विदेशी प्रतिनिधियों के आने से हमें काफी बल मिलेगा और हमारे फेडरेशन की अन्तर्राष्ट्रीय छवि बनेगी। →

चीनी प्रतिनिधि मण्डल का आगरा आगमन

Mr. Cui Zhongfu

Mr. Qin Yuming

Chinese प्रतिनिधि मण्डल 16 व 17 जुलाई, 2016 की मीटिंग में आगरा आ रहा है। हमें अत्यन्त वर्ष के साथ सूचित कर रहे कि China Cold Chain के delegate हमारी आगरा की मीटिंग में आ रहे है। यह प्रतिनिधि मण्डल दस व्यक्तियों का होगा। इनके भी Clarks Shiraz Hotel में ठहरने की व्यवस्था की गई है। Chinese Federation of Logistics and Purchasing के Vice President और Secretary General Mr. Cui Zhongfu व कोल्ड Chain Logistics Committee of China Federation of Logistics and Purchasing के Secretary General Mr. Qin Yuming चित्र ऊपर दिए गए है। हम आशा करते है कि हमारे सदस्य China Cold Chain के बारे में गहन जानकारी हासिल कर सकेंगे।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित